रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2001/श्रावण 3, 1923
No. 200] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2001/SRAVANA 3, 1923

## विनिवेश विभाग

### संकल्प

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2001

फा. सं. 11012/1/2000-प्रशा.--सरकार सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का आरंभिक रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा पुनर्गठन करती है।

2. आयोग का नेतृत्व, अध्यक्ष डा. आर. एच. पाटिल द्वारा किया जाएगा। आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति अलग से की जाएगी।

3. आयोग के व्यापक विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(i) यह एक परामर्शदायी निकाय होगा तथा इसकी भूमिका व कार्य सरकार को सरकारी क्षेत्र के उन एककों में विनिवेश के बारे में परामर्श देना होगा, जो सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गए हैं।

(ii) यह विनिवेश संबंधी किसी अन्य मामले पर भी सरकार को परामर्श देगा जो सरकार द्वारा इसे विशेष रूप से सौंपे जाएं, तथा सरकार द्वारा सौंपे गए विनिवेश संबंधी ऐसे अन्य कार्यकलाप भी करेगा।

(iii) अपनी अनुशंसा करते समय यह सरकारी क्षेत्र के एकक (एककों) के कामगारों, कर्मचारियों तथा अन्य शेयरधारकों के हितों को भी ध्यान रखेगा।

(iv) विनिवेश आयोग की अनुशंसाओं पर अंतिम निर्णय सरकार के पास निहित रहेगा।

के. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

## DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

### RESOLUTION

New Delhi, the 24th July, 2001

**F. No. 11012/1/2000-Admn.**—The Government hereby re-constitutes the Public Sector Disinvestment Commission, initially for a period of two years.

2. The Commission will be headed by Chairman Dr. R. H. Patil. The other Members of the Commission will be appointed separately.

3. The broad terms of reference of the Commission are as follows :

(i) It shall be an advisory body and its role and function would be to advise the Government on Disinvestment in those public sector units that are referred to it by the Government.

(ii) It shall also advise the Government on any other matter relating to disinvestment as may specifically be referred to it by the Government, and also carry out any such other activities relating to disinvestment as may be assigned to it by the Government.

(iii) In making its recommendations, it will also take into consideration the interest of workers, employees and other stakeholders, in the public sector unit(s).

(iv) The final decision on the recommendations of the Disinvestment Commission will vest with the Government.

K. K. GUPTA, Jt. Secy.

2292 GI/2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.